ईस्ट इंडिया कोल कंपनी लिमिटेड

बनाम

ईस्ट बुलियारी केंदवाडीह कोलियरी कंपनी पी लिमिटेड और अन्य

3 मार्च 1987

(ओ चिन्नप्पा रेड्डी एवं वी खालिद, जेजे)

कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 धाराएँ 3, 4, 5, 12 ए, 23 और 24 -मालिक- कौन है - मुआवजा - का दावा - बंटवारे का हिस्सा - बंटवारे के लिए दिशानिर्देश संकेत दिया।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 कोयला खदानों के कोकिंग कोल के उभरते ठेकेदारों और बिक्री एजेंटों के रूप में कारोबार कर रहे थे। अप्रयुक्त खदानों के संबंध में कोयला जुटाने और बेचने और हार्ड कोक बनाने के लिए ठेकेदार नियुक्त करने वाली अपीलीय कंपनी के साथ एक समझौते के अनुसार, उन्होंने भारी लागत पर मूल्यवान मशीनरी, बर्तन और केक ओवन स्थापित किए।

कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) 1972 अधिनियम द्वारा कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण पर सभी खाने सरकार मे निहित हो गई प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने चैथे प्रतिवादी के साम्मुक अधिनियम की धारा 26 के तहत एक दावा पेश किया जा कर कमिश्नर ऑफ पेमेंट, अधिनियम के

तहत गठित वैधानिक प्राधिकरण था उच्च न्यायालय में भी एक रिट याचिका के माध्यम से यह दलील दी कि वे विवादित कुछ खदानों के मालिक भी थे और मुआवजे में उनके शेयर के हकदार थे और एक निर्देश के लिए प्रार्थना की कि उन्होंने मशीनरी के लिए बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया, प्लांट, उपकरण, बिल्डिंग, स्टोर आदि। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने रिट याचिका की अनुमति दी और कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 अधिनियम के तहत मालिक थे और प्रतिवादी संख्या 4 को कानून के अनुसार दावे के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता द्वारा अपील खारिज करते हुए इस कोर्ट ने निम्नानुसार प्रतिपादित किया

अभीनिर्धारित: 1. अधिनियम की धारा 4 और 5 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकार, शीर्षक, प्रथम अनुसूची में निर्धारित खानों और कोक ओवन संयंत्रों के संबंध में मालिकों का हित और केन्द्र सरकार में दूसरी अनुसूची निहित नियत दिन पर सभी परिव्यय से मुक्त। (491 एचय 492),

2.1. 'मालिक' शब्द को धारा 3 (ए) में परिभाषित किया गया है। परिभाषा से यह स्पष्ट है कि यह खदान या उसके किसी हिस्से पर कब्जे के दायरे मे ले लेता है। 'मालिक' शब्द की परिभाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि खान के संबंध में धारा 3 (एन) के अर्थ के भीतर एक से अधिक

'मालिक' हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रथम अनुसूची के कॉलम 5 में दिखाई गई राशि के एक हिस्से का हकदार होगा। ठेकेदारों को खड़ा करना भी एक्ट में 'मालिक' की अभिव्यक्ति के दायरे में आएगा। इसलिए वे जमा किए गए मुआवजे के प्रोराटा वितरण के भी हकदार हैं। (497 –□ –एक्र

मौजूदा मामले में इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने स्वीकार ठेकेदार हैं उनके संचालन के लिए खदानों के कम से कम हिस्से पर कब्जा कर रहे थे और इस प्रकार परिभाषा के भीतर एक कब्जाकर्ता थे। वे परिभाषा अनुभाग में बहिष्करण खंड के भीतर नहीं आते। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 अधिनियम की धारा 3(एन) की परिभाषा के डायरे मे' ' (490 सी-डी)

इंडस्ट्रियल सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1980, 4 एससीसी 341, पर भरोसा किया गया।

2.2. अधिनियम के अध्याय में आने वाली धारा 20(1) और 21(1) से (5) में जानबूझकर 'पहली अनुसूची में मालिकों की अभिव्यक्ति से परहेज किया गया है ताकि' ' , 1952 मे है को प्राप्त कर सके, जो परिभाषा इसके द्वारा भौतिक रूप से उधार ली गई है कार्यवाही करना। यदि वह स्वामी जिसका नाम कॉलम 4 में उल्लिखित है अकेले मुआवजे का हकदार, अध्याय चार की धाराओ मे प्रभाजन की आवश्यकता नहीं थी (494 ई-एफ)

3.1. धारा 12 ए मालिक को जिन्होंने श्रमिकों को नियोजित किया है, को उनके वेतन और अन्य देय राशि के लिए उत्तरदायी बनाती है और इसमें दावा करने की प्रक्रिया, उसका प्रमाण और निर्धारण शामिल है। जैसा कि उपधारा (6) में बताया गया हैं इन बकाया राशि के संबंध में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस धारा के तहत भुगतान को अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता दी जाएगी चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। इसे धारा 23(2) द्वारा और भी स्पष्ट किया गया है। (496 सी-डी)

3(ii) सुरक्षित लेनदार प्राथमिकता में आगे आते हैं, और श्रमिकों को देय राशि के अधीन उनके बकाया के बारे में प्राथमिकता होगी। (496 डी3(iii) अधिनियम के तहत देय मुआवजे की राशि, केंद्र सरकार द्वारा आयुक्त के स्तर पर भुगतान का निपटान के लिए रखा जाता है। धारा 23 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका मालिक के खिलाफ दावा है, वह निर्धारित अवधि के भीतर आयुक्त के समक्ष दावा कर सकता है। (496 ई-एफ)

3(v) धारा 23(4)से (9)मालिक के खिलाफ दावेदारों पर विचार करने और सुनने को प्रक्रिया प्रतिपादित करती है। इसमें दावेदारों के साथ ही आयुक्त के समक्ष मालिक को भी सुनाने का मौका देने का प्रावधान है। आयुक्त के निर्णय अपील का विषय है अपीलीय न्यायालय प्रधान सिविल

न्यायालय होती है जो खदान जहां स्थित है उसी स्थानीय सिविल क्षेत्राधिकार आता है(496 एच: 497 ए-बी)

4. सेक्शन 25 खदानों के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अग्रिम भुगतान के प्रावधानों को परिभाषित करता है। उससे यह निर्धारित होता है की खदान से प्राप्त आय में से वह अवधि जिसके दौरान स्वामित्व निहित होने तक वह केंद्र सरकार के प्रबंधन में रहा यह या यदि अग्रिम राशि वसूल नहीं की गई है तो केंद्र सरकार इससे पहले दावा करने में सक्षम है आयुक्त और इस दावे को प्राथमिकता दी जाएगी खदान के अन्य सभी असुरक्षित लेनदारों को दावे से उक्त अवधि के लिए वसूल की जाएगी। (497 सी-डी)

5. धारा 26 उन मामलों से संबंधित है जहां संदेह या विवाद उठता है जो उस व्यक्ति की लड़ाई के बारे में उठता है जो इसका मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है तथा आयुक्त द्वारा दावे को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में भेजा जाएगा। (497 ई-एफ)

6. धारा 23 एवं 24 को उचित तरीके से समझाने के लिए यह है की स्वीकृत दावों में कटौती की जा सकती है देय राशि से केवल तभी जब ऐसा दावा मालिक से संबन्धित हो दूसरे शब्दों में, यह केवल स्वामी ही है जिसने उक्त ऋण वहन किया है जिसका भुगतान उसी को करना होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्ज की मात्रा कितनी है। किसी भी

मालिक की मुआवजा राशि से कटौती नहीं की जाये जो है. दूसरे मालिक को देय हो, जिस पर उसके पैसा बकाया नहीं है। (498 डी-ई)

7(1) धारा 25 ए देनदारियों को पूरा करने के बाद शेष राशि के वितरण से संबंधित है । इसे आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रत्येक मालिक के अधिकारों के अनुसार वितरित किया जाना है और विवाद की स्थिति में विवाद एक सक्षम न्यायालय में भेजना होगा। (499 डी-ई)

7.2. आयुक्त को हिस्सेदारी का निर्धारण करना होगा (उत्तरदाताओं द्वारा दावा किए गए खदान के मुआवजे का 1 और 2 धारा 26(2) के अनुसार) (499 एचय: 500 ए)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3118/1982

सिविल रिट याचिका संख्या 112 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.8.1982 से।

एस.एन. कक्कड़ और एच.के. पुरी अपीलार्थी की ओर से ।

शांति भूषण, श्री एस.एस. जौहर, सी.एल. साहू और एम.एल. वर्मा उत्तरदाताओं के और से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधीस खालिद, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (संक्षेप में 'अधिनियम') द्वारा किया

गया था। इस अधिनियम के तहत, 1 मई, 1972 से खदानें सरकार में निहित हो गईं। अधिनियम में राष्ट्रीयकरण योजना के तहत आने वाली विभिन्न खदानों को दर्शाने वाली एक अनुसूची शामिल है। इस अपील में शामिल खदानों को अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्या 112 से 116 के रूप में दिखाया गया है। अनुसूची, इसके अलावा, खानों का स्थान, खानों के मालिकों का नाम और पता और मुआवजे की राशि भी दर्शाती है। अपील में शामिल खदानों के चैथे कॉलम में मालिकों का नाम ईस्ट इंडिया कोल कंपनी लिमिटेड, हमारे सामने अपीलकर्ता और कुल मुआवजा रुपये राशि के रूप मे दिखाया गया 93,23,500.

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 कार्यरत कोयला खदानों के कोकिंग कोयले के ठेकेदारों और उभरते बिक्री एजेंटों के रूप मे का व्यवसाय कर रहे थे। उनके अनुसार, मेसर्स जार्डिन हैंडसन लिमिटेड, जो अपीलकर्ता कंपनी के प्रबंध एजेंट थे, ने एक समझौते के अनुसार, उन्हें कोयला जुटाने और बेचने और अप्रयुक्त खदानों के संबंध में हार्ड कोक का निर्माण करने के लिए ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया। यह आरोप लगाया गया था कि समझौते के तहत वे ठेकेदारों के रूप में अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए संयंत्र, मशीनरी और अन्य उपकरण स्थापित करने के हकदार थे। इस समझौते के अनुसार, उन्होंने भारी लागत पर मूल्यवान मशीनरी, बर्तन और कोक ओवन स्थापित किए। राष्ट्रीयकरण के बाद, उन्हें लगा कि मुआवजे में

उनके उचित हिस्से को अपीलकर्ता कंपनी से प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इसलिए, उन्होंने चैथे प्रतिवादी, भुगतान आयुक्त, कोकिंग कोल माइंस, जो अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकारी है, के समक्ष अधिनियम की धारा 26 के तहत दावा दायर किया। उन्होंने रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि अधिनियम के तहत वे भी खदानों के मालिक थे और मुआवजे में अपने हिस्से के हकदार थे और उन्होंने यह निर्देश देने की प्रार्थना की कि उन्हें मशीनरी के लिए बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाए। संयंत्र, उपकरण, भवन, भंडार आदि और इसके अलावा अधिनियम की वैधता को चुनौती दी। अधिनियम की वैधता के खिलाफ चुनौती निरर्थक हो गई क्योंकि अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रखा गया था। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने रिट याचिकाकर्ताओं प्रतिवादी 1 और 2 की याचिका स्वीकार कर ली और माना कि ये दोनों अधिनियम के तहत मालिक थे और चैथे प्रतिवादी को कानून के अनुसार दावे के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील विशेष अनुमति द्वारा दायर की गई है

हमारे सामने अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपनी चुनौती में इस निष्कर्ष पर विवाद किया कि उत्तरदाता 1 और 2 भी अधिनियम के तहत मालिक थे और इस बात से इनकार करते हैं कि उनके

पास संयंत्र और मशीनरी या उपकरण के किसी भी हिस्से का स्वामित्व था जिसे राष्ट्रीयकरण के तहत ले लिया गया था।

मामला अब चैथे प्रतिवादी के समक्ष लंबित है, जो अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकारी है। उसे दावों के बारे में निर्णय लेना होगा और यदि आवश्यक हो तो मामले को सक्षम सिविल अदालत में भेजना होगा, यदि किसी व्यक्ति के संपूर्ण राशि या उसके कुछ हिस्से को प्राप्त करने के अधिकार के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता तो हम दावे के प्रभाजन भाग में नहीं जा सकते। इस अपील में हमें बस अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के बीच विवाद को सुलझाना है कि अधिनियम के तहत खदानों का मालिक कौन है। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाताओं 1 और 2 को छोड़कर अपीलकर्ता खदानों के मालिक हैं या नहीं। फिर हमें यह बताना होगा कि मालिकों द्वारा देय ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाना है और किस ऋण को अन्य ऋणों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। यह हमें कुछ धाराओं के संदर्भ में अधिनियम की योजना की जांच करने के बाद करना होगा।

पहला प्रश्न तो यह है कि प्रश्नगत खदान का मालिक कौन है? अपीलकर्ताओं का तर्क है कि मुआवजे की राशि को लेकर उनका विशेष झगड़ा है जबकि प्रतिवादी 1 और 2 का दावा है कि इसमें उनका हिस्सा है। हम इस विवाद को सुलझाने के लिए हमारे संज्ञान में लाए गए अनुभागों

का उल्लेख करेंगे। इस उद्देश्य के लिए धारा 4, 5, 3(एन), 10 और 12 को उपयोगी रूप से देखा जा सकता है।

धारा 4(1) घोषित करती है कि खदानों के संबंध में मालिकों का अधिकार, स्वामित्व, हित सभी बाधाओं से मुक्त होकर, नियत दिन पर केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह इस प्रकार पढ़ता हैः

> ‘‘4(1)नियत दिन पर, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कोकिंग कोयला खदानों के संबंध में मालिकों की लड़ाई, स्वामित्व और हित सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे’’

इसी प्रकार, धारा 5 इस धारा के संचालन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कोक ओवन संयंत्रों के मालिकों की लड़ाई के अधिग्रहण को संदर्भित करती है। धारा 5 इस प्रकार हैः

> ‘‘5. नियत दिन पर, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कोक ओवन संयंत्रों में से प्रत्येक के मालिकों के अधिकार, शीर्षक और हित, वे कोक ओवन संयंत्र हैं जो पहली अनुसूची में

निर्दिष्ट कोकिंग कोयला खदानों में या उनके आसपास स्थित हैं, को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित हो जाएगा।''

इसलिए, इन दोनों खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्धारित खदानों और कोक ओवन संयंत्रों के संबंध में मालिकों का अधिकार, स्वामित्व, हित नियत दिन पर सभी बाधाओं परे केंद्र सरकार में निहित है।

यह हमें इस प्रश्न पर ले जाता है कि इन दोनों वर्गों द्वारा विचार करने पर स्वामी कौन है। 'मालिक' शब्द को धारा 3(एन) में परिभाषित किया गया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

''3(एन) 'मालिक'

(i) जब किसी खदान के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो उसका वही अर्थ होता है जो खान अधिनियम, 1952 में दिया गया है।

(ii) जब कोक ओवन संयंत्र के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कोक ओवन संयंत्र या उसके किसी भी हिस्से के पट्टेदार या अधिभोगी का तत्काल मालिक है या उसके किसी भी हिस्से के कोक ओवन संयंत्र के काम के लिए ठेकेदार है। ।''

इसलिए, किसी खदान के संबंध में 'मालिक' शब्द की परिभाषा के लिए, हमें खान अधिनियम, 1952 में दी गई परिभाषा की जांच करनी होगी। यह इस प्रकार हैः

''2(1)(1) 'मालिक' जब किसी खदान के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति है जो खदान या उसके किसी भी हिस्से के पट्टेदार या कब्जेदार का तत्काल मालिक है और खदान के मामले में उसका व्यवसाय है किसी परिसमापक या रिसीवर द्वारा किया जा रहा है, ऐसे परिसमापक या रिसीवर और किसी कंपनी के स्वामित्व वाली खदान के मामले में, जिसका व्यवसाय एक प्रबंध एजेंट, ऐसे प्रबंध एजेंट द्वारा किया जा रहा है लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने केवल खदान से रॉयल्टी, किराया या जुर्माना प्राप्त किया है या खदान का मालिक मात्र वहां काम करने के लिए किसी पट्टे, अनुदान या लाइसेंस के अधीन

है, या केवल उक्त खदान का मालिक है और खदान के खनिजों में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन किसी खदान या उसके किसी हिस्से के काम के लिए कोई भी ठेकेदार इस अधिनियम के अधीन उसी तरह होगा जैसे कि वह एक मालिक था, लेकिन मालिक को किसी भी दायित्व से छूट देने के लिए नहीं।

परिभाषा से स्पष्ट है कि यह अपने दायरे में 'खदान या उसके किसी हिस्से पर कब्जा करने वाले को लेता है. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि यहाँ प्रतिवादी 1 और 2, एक ठेकेदार के रूप मे, अपने संचालन के लिए खदान के कम से कम एक हिस्से पर कब्जा कर रखा था और इस प्रकार परिभाषा के भीतर एक कब्जाकर्ता था। वे परिभाषा अनुभाग में बहिष्करण खंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि उत्तरदाता 1 और 2 अधिनियम की धारा 3(एन) की परिभाषा के तहत मालिक हैं। हमारे इस निष्कर्ष के लिए, हम औद्योगिक आपूर्ति प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1980) 4 के मामले में तीन न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा दिए गए इस न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हैं, जिसमें हम में से एक पक्ष था। एससीसी 341. इंडेंटिकल सेक्शन की व्याख्या करते हुए, एपी सेन, जे, ने बेंच के लिए बोलते हुए इस प्रकार कहाः

“22. यह दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता वास्तव में प्रबंध ठेकेदार नहीं थे, लेकिन समझौते में इसे गलत तरीके से वर्णित किया गया था..... याचिकाकर्ताओं को कोयला जुटाने, प्राप्त करने के लिए खदान में काम करने के लिए सभी अधिकार प्रदान की गईं। उन्हें देय तथाकथित पारिश्रमिक वास्तव में आपूर्ति किए गए कोयले की कीमत थी, जिससे मालिकों को लाभ का मार्जिन मिल जाता था... याचिकाकर्ताओं ने खुद को समझौते की शर्तों से बांध लिया था, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती। धारा 4 की उपधारा (1) के प्रावधानों से बचने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3(एन) में ‘मालिक’ की परिभाषा के दायरे में आते हैं।

23. वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया जाता है कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 2(1) के साथ पढ़े जाने वाले राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3(एन) में परिभाषित ‘मालिक’ शब्द किसी भी स्थिति में शामिल नहीं है। उभरते ठेकेदार यह सुझाव नहीं दिया गया है कि धारा 2(1) में एक ठेकेदार के विवरण में नहीं आता है ऐसा धारा 2(1) मे सुझाव नहीं है, लेकिन यह तर्क दिया गया है कि ‘शामिल’ शब्द वहां नहीं है। ‘जैसे कि वह थ शब्दों के कारण संसद को‘इन क्लूड्स शब्द डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि आम बोलचाल में ‘मालिक’ शब्द, अपने

सामान्य अर्थ में, एक खदान के स्वामित्व को दर्शाता है, इस शब्द को कानूनी अर्थ में समझा जाना चाहिए, जैसे कि

24. संसद ने उचित विचार-विमर्श के साथ, राष्ट्रीयकरण अधिनियम को सर्वव्यापी और पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 2(1) में मालिक की विस्तृत परिभाषा को शामिल करके धारा 3(एन) में अपनाया। यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है; (i) किसी खदान के संबंध में, वह व्यक्ति जो मेरा या उसके किसी हिस्से का तत्काल मालिक या पट्टेदार या कब्जाधारी है, (ii) किसी खदान के मामले में जिसका व्यवसाय परिसमापक या रिसीवर द्वारा किया जाता है, ऐसा परिसमापक या रिसीवर, और (iii) किसी कंपनी के स्वामित्व वाली खदान के मामले में, जिसका व्यवसाय एक प्रबंध एजेंट, ऐसे प्रबंध एजेंट द्वारा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग और अलग श्रेणी है और स्वामित्व की अवधारणा इसमें नहीं आती है। फिर महत्वपूर्ण अंतिम शब्द आते हैं; "लेकिन किसी खदान या उसके किसी हिस्से के काम के लिए कोई भी ठेकेदार इस अधिनियम के अधीन उसी तरह होगा जैसे कि वह एक मालिक था, लेकिन मालिक को किसी भी दायित्व से छूट देने के लिए नहीं।" इस खंड को शामिल करने से मालिक और ठेकेदार दोनों को अधिनियम के

उचित पालन के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है। इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि खान अधिनियम, 1952 में खानों और उनमें कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। किसी खदान के मामले में, जिसका काम एक ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, वह मुख्य रूप से अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि किसी खदान या उसके किसी हिस्से के काम के लिए ठेकेदार मालिक नहीं है, वह अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा, उसी तरह जैसे कि वह एक मालिक था, लेकिन ऐसा नहीं कि मालिक को किसी भी छूट से छूट मिल जाए। देयता।"

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उत्तरदाताओं 1 और 2 को मुआवजे में किसी भी अधिकार से वंचित करने के अपने प्रयास में, पहली और दूसरी अनुसूची में दिखाए गए नामों से समर्थन मांगा, जो उनके अनुसार स्पष्ट रूप से इंगित करता था कि कोयला खदानों का मालिक कौन था और बनाया गया था उनका निवेदन इस प्रकार है: पहली अनुसूची में खदान का स्थान और मालिक का नाम दिया गया है। धारा 4 पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मालिकों को ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित करती है जिसका अधिकार, शीर्षक और हित नियत दिन पर केंद्र सरकार में निहित होंगे। धारा 4(3) जो एक संशोधित धारा है, केंद्र सरकार को पहली अनुसूची में शामिल कोकिंग कोयला खदान के विवरण या ऐसे किसी भी कोकिंग के

मालिक के नाम और पते के संबंध कोले की खान में किसी भी त्रुटि, चूक या गलत विवरण को ठीक करने की शक्ति देती है। धारा 5 दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक कोक ओवन संयंत्र के मालिक को भी संदर्भित करती है। वह इस तथ्य पर जोर देना चाहते हैं कि ये धाराएं अनुसूची में उल्लिखित मालिकों के नाम का उल्लेख करके उन लोगों को बाहर करना चाहती हैं जिनका इसमें उल्लेख नहीं है।

फिर वह उसी उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 10 पर निर्भर करता है; धारा 10 इस प्रकार है:

> "10. कोकिंग कोयला खदानों के मालिकों को राशि का भुगतान: पहली अनुसूची के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट प्रत्येक कोकिंग कोयला खदान या कोकिंग कोयला खदानों के समूह के मालिक को केंद्र सरकार द्वारा नकद और तरीके से भुगतान किया जाएगा धारा 21 में निर्दिष्ट, धारा 4 के तहत, ऐसी कोकिंग कोयला खदान या कोकिंग खदानों के समूह के संबंध में मालिक के अधिकार और हित को इसमें निहित करने के लिए, संबंधित प्रविष्टि में इसके सामने निर्दिष्ट राशि के बराबर राशि उक्त अनुसूची का पाँचवाँ स्तम्भ।" के अनुसार दी जाएगी

यहां भी, अनुभाग दर्शाता है कि मुआवजे की राशि पहली अनुसूची के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट कोकिंग कोयला खदान के मालिक को दी जानी है। इसी उद्देश्य के लिए धारा 12 पर भी भरोसा रखा गया था। धारा 12(1) और धारा 12(2) भी पहली अनुसूची में उल्लिखित मालिक को संदर्भित करती है। धारा 12(1) और 12(2) को उद्धृत करना बेहतर है:

> "12(1) धारा 4 और धारा 5 के प्रावधानों के पूर्वव्यापी संचालन पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक कोकिंग कोयला खदान के मालिक को नकद में दिया जाएगा। दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कोक ओवन संयंत्र, उस राशि के बराबर राशि, जो कोकिंग कोयला खदान (आपातकालीन) के तहत ऐसे मालिक को देय होगी, लेकिन उक्त धारा 4 या धारा 5 के प्रावधानों के लिए, जैसा भी मामला हो प्रावधान) अधिनियम, 1971, 1 मई 1972 से शुरू होने वाली और सहमति की तारीख पर समाप्त होने वाली अवधि के लिए।
>
> (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक कोकिंग

कोयला खदान के मालिक और प्रत्येक कोक ओवन संयंत्र के मालिक को नकद में दिया जाएगा। दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के पांचवें कॉलम में संबंधित प्रविष्टि में ऐसे मालिक के खिलाफ निर्दिष्ट राशि पर, जैसा भी मामला हो, शुरू होने वाली अवधि के लिए चार प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सहमति की तिथि पर और आयुक्त को ऐसी राशि के भुगतान की तिथि पर समाप्त होने पर''

हालाँकि, इन प्रस्तुतियों से उत्साहित होकर, उन्होंने अधिनियम की धारा 20 द्वारा उत्पन्न कठिनाई को पूरा करने का साहस किया, जिसमें धारा 4, 5, 10 और 12 के समान वाक्यांश का उपयोग नहीं किया गया है। अध्याय VI भुगतान आयुक्त से संबंधित है। इस अध्याय में धारा 20(1) के द्वारा, केंद्र सरकार को भुगतान आयुक्त नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। यह देखने के लिए कि इसे कैसे शब्दों में लिखा गया है, इस अनुभाग को पढ़ना आवश्यक है।

> ‘‘20(1) प्रत्येक कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवर प्लांट के मालिक को देय राशि के वितरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जिसे वह भुगतान आयुक्त के रूप में उपयुक्त समझे।‘‘

इस खंड में प्रयुक्त पदावली तुरंत ही किसी का ध्यान खींच लेती है। यहां प्रयुक्त शब्द हैं ‘‘प्रत्येक कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र के मालिक को देय राशि । ‘मालिक’ शब्द ‘‘पहली अनुसूची के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति के साथ योग्य नहीं है। इसी अध्याय की धारा 21 भी इस चर्चा के लिए उपयोगी है। यह पढ़ता हैः

> ‘‘21(1)। केंद्र सरकार, निर्दिष्ट तिथि से तीस दिनों के भीतर, आयुक्त को नकद भुगतान करेगी, या मालिक या कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र को निर्दिष्ट राशि के बराबर राशि का भुगतान करेगी। कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में, धारा 12 में निर्दिष्ट राशि और ब्याज, यदि कोई हो, के साथ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि के अलावा, केंद्र सरकार, आयुक्त को नकद में, ऐसी राशि का भुगतान करेगी जो कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र के मालिक को देय हो सकती है। वह राशि जिसके दौरान कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र का प्रबंधन केंद्र सरकार में निहित रहा।'' हैं

धारा 21(1) और 21(2) में कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र का मालिक ''पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट'' अभिव्यक्ति के साथ योग्य नहीं है। धारा 21(3) अधिनियम के तहत नियुक्त आयुक्त को प्रत्येक कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र के संबंध में एक अनुसूचित बैंक में एक खाता खोलने और संचालित करने का निर्देश देती है। धारा 21(4) में कहा गया है कि आयुक्त मुआवजे की राशि कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र के खाते के क्रेडिट में जमा करेगा जिससे भुगतान संबंधित है, और धारा 21(5) में कहा गया है कि राशि पर अर्जित ब्याज खाते में जमा राशि कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र, जैसा भी मामला हो, के मालिक के लाभ के लिए सुनिश्चित की जाएगी। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन उपधाराओं में मालिक को

पहली अनुसूची के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट मालिक के नाम से निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

इस प्रकार, उपरोक्त अनुभागों में इस विनिर्देश की अनुपस्थिति अपीलकर्ताओं के लिए कठिनाई पैदा करती है। श्री काकर ने यह तर्क देकर इस कठिनाई से बाहर निकलने का प्रयास किया कि श्पहली अनुसूची में निर्दिष्ट स्वामी की अभीव्यक्ति को इन अनुभागों में भी पढ़ा जाना चाहिए, भले ही वे वहां अनुपस्थित हों। ऐसी दलील पर प्रतिवादी 1 और 2 को किसी भी झगड़े से इनकार करने का यह प्रयास, हमारे विचार में, सफल नहीं हो सकता है। अध्याय छ में आने वाली धाराओं ने जानबूझकर ष्पहली अनुसूची में मालिकोंष् की अभिव्यक्ति से परहेज किया है ताकि खान अधिनियम, 1952 में श्मालिक की परिभाषा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जो परिभाषा इस अधिनियम द्वारा भौतिक रूप से उधार ली गई है। हम ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के फैसले से सहमत होते हुए इस चर्चा को समाप्त करते हैं, कि उत्तरदाता 1 और 2 भी कब्जेदार के रूप में मालिक हैं। यदि मालिक जिसका नाम कॉलम 4 में उल्लिखित है, अकेले मुआवजे का हकदार है, तो विभिन्न खंडों पर विचार करने के बाद राशि के बंटवारे के लिए अध्याय छ में शेष खंडों की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अब जो कुछ बचा है, वह उन प्राथमिकताओं के संबंध में आयुक्त को दिशानिर्देश देना है जिसमें खदान मालिकों द्वारा देय ऋण का भुगतान किया जाना है। धारा 12 ए श्रमिकों के बकाए से संबंधित है। जो कहती हैं

"12 ए-श्रमिकों का बकाया राशि में से भुगतान किया जाएगार.

(1) देय राशि में से-

(ए) धारा 10 और धारा 12 के तहत प्रत्येक कोकिंग कोयला खदान या कोकिंग कोयला खदानों के समूह के मालिक कोय

(बी) प्रत्येक कोक ओवन संयंत्र के मालिक को धारा 11 और धारा 12 के तहत, ऐसे मालिक द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, नियत दिन पर, ऐसे कर्मचारी को देय बकाया राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा,

(i) भविष्य निधि, पेंशन निधि के संबंध मेंय ग्रेच्युटी फंड या ऐसे कर्मचारी के कल्याण के लिए स्थापित कोई अन्य फंडय और

(ii) मजदूरी के रूप में।

(2) प्रत्येक कर्मचारी जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपूर्ण या आंशिक बकाया है, कोकिंग और नॉनकोकिंग कोयला खदानों (राष्ट्रीयकरण) के शुरू होने के बाद, ऐसे समय के भीतर आयुक्त को अपने दावे का प्रमाण दाखिल

करना होगा।) संशोधन अधिनियम, 1973, जैसा कि आयुक्त तय कर सकते हैं।

(3) धारा 23 के प्रावधान, उपधारा (2) में निर्दिष्ट सबूतों को दाखिल करने, स्वीकार करने या अस्वीकार करने पर लागू होंगे।

(4) आयुक्त, उपधारा (2) के तहत किए गए दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के बाद, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बकाया की कुल राशि का निर्धारण करेगा, और इस तरह के निर्धारण के बाद, पहली बार में, धारा 21 के तहत उसे भुगतान की गई राशि में से, ऐसे बकाया की कुल राशि के बराबर राशि की कटोती करेगा

(5) उपधारा (4) के तहत आयुक्त द्वारा काटी गई सभी रकम, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, आयुक्त द्वारा संबंधित निधि में जमा की जाएगी या उन व्यक्तियों को भुगतान की जाएगी जिनके लिए ऐसी रकम बकाया है, और इस तरह के क्रेडिट या भुगतान पर, कोकिंग कोयला खदान या कोकिंग कोयला खदानों के समूह या कोक सम संयंत्र के मालिक की देनदारी, जैसा भी मामला हो, उपरोक्त देय बकाया राशि के संबंध में, उन्मोचित हो जाएगी।

(6) उपधारा (4) के तहत आयुक्त द्वारा की गई कटौती को अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित।

(7) जैसा कि पूर्वगामी उपधाराओं में अन्यथा प्रदान किया गया है, को छोड़कर, कोकिंग कोयला खदान या कोकिंग कोयला खदानों के समूह या कोक ओवन संयंत्र के मालिक से देय प्रत्येक सुरक्षित ऋण, जैसा भी मामला हो, अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता होगी और होगी सुरक्षित लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।''

यह धारा उस मालिक को, जिसने श्रमिकों को नियोजित किया है, उनके वेतन और अन्य देय के लिए उत्तरदायी बनाता है। इस अनुभाग में दावा करने की प्रक्रिया, उसका प्रमाण और निर्धारण शामिल है। इन बकाया राशि के संबंध में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जैसा कि उपधारा (6) में प्रदान किया गया है कि इस धारा के तहत भुगतान को अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता दी जाएगी चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। इसे धारा 23(2) द्वारा और भी स्पष्ट किया गया है। सुरक्षित ऋणदाता प्राथमिकता में अगले स्थान पर आते हैं। श्रमिकों को देय राशि के अधीन उनके बकाए के संबंध में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

अब अन्य दावों पर आते हुए, हम संबंधित अनुभागों की संक्षेप में जांच करेंगे। अधिनियम के तहत देय मुआवजे की राशि केंद्र सरकार द्वारा भुगतान आयुक्त के निपटान में रखी जाती है। धारा 23 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका मालिक के खिलाफ दावा है, वह निर्धारित अवधि के भीतर आयुक्त के समक्ष दावा कर सकता है। हम पहले ही नोट कर चुके हैं

कि धारा 23(2) वेतन और वेतन की प्रकृति, भविष्य निधि अधिनियम के तहत देय योगदान की राशि, श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत देय राशि, कर्मचारियों को देय राशि, ऋण के भुगतान की प्राथमिकता प्रदान करती है। पेंशन, ग्रेच्युटी से. इसके अलावा यह धारा राज्य सरकार को रॉयल्टी, किराया या अनिवार्य किराया के रूप में देय रकम की बात करती है। धारा 23(3) में प्रावधान है कि ऊपर उल्लिखित उपधारा (2) के तहत देय राशि को आपस में समान रूप से रैंक किया जाएगा और पूरा भुगतान किया जाएगा और यदि संपत्ति पर्याप्त नहीं है, तो देय शेष राशि कम हो जाएगी। इस अनुभाग को धारा 12ए(6) और (7) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। राज्य सरकार को देय राशि कर्मचारियों और सुरक्षित लेनदारों को देय राशि के अधीन होगी, क्योंकि धारा 23(2) अन्य सभी असुरक्षित ऋणों की प्राथमिकता में उसमें उल्लिखित ऋणों के भुगतान की बात करती है। धारा 23(4) से (9) मालिक के खिलाफ दावों पर विचार करने और सुनवाई की प्रक्रिया बताती है। आयुक्त के समक्ष दावा करने वाले दावेदारों के साथ-साथ मालिक को भी सुनने का प्रावधान है। आयुक्त का निर्णय अपील के अधीन है, अपीलीय न्यायालय मूल नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रधान नागरिक न्यायालय है जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर संबंधित खदान स्थित है। धारा 24 में प्रावधान है कि जहां आयुक्त द्वारा स्वीकार किए गए दावे की कुल राशि अधिनियम के तहत मालिक को देय राशि से अधिक नहीं है, तो

स्वीकृत दावे की राशि पूरी तरह से भुगतान की जाएगी और शेष राशि मालिक को भुगतान की जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि जब स्वामी को देय राशि स्वीकृत दावे की पूर्ण और कुल मांग को पूरा करने के लिए कम पड़ जाती है तो ऐसे प्रत्येक दावे को समान अनुपात में समाप्त कर दिया जाएगा और तदनुसार भुगतान किया जाएगा। धारा 25 खदान के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अग्रिम राशि के भुगतान का प्रावधान करती है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी रकम या तो उस अवधि में खदान से प्राप्त आय से वसूल की जा सकती है, जिसके दौरान वह स्वामित्व प्राप्त होने तक केंद्र सरकार के प्रबंधन के अधीन रही, या यदि अग्रिम राशि वसूल नहीं की गई है तो। केंद्र सरकार आयुक्त के समक्ष दावा करने में सक्षम है और इस दावे को खदान के अन्य सभी असुरक्षित लेनदारों के दावे पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस दावे पर विचार करते समय, आयुक्त को यह देखना होगा कि किस मालिक को अग्रिम भुगतान किया गया था, और इस तथ्य को सुनिश्चित करने के बाद, ऐसे मालिक को अग्रिम के लिए उत्तरदायी बनाना होगा।

धारा 26 उन मामलों से संबंधित है जहां मुआवजा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अधिकार के बारे में संदेह या विवाद उत्पन्न होता है। धारा में प्रावधान है कि आयुक्त दावे को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को संदर्भित करेगा, जिसका कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र

के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान सिविल न्यायालय है, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर कोकिंग कोयला खदान या कोक ओवन संयंत्र है। जेसा की धारा 10, 11 और 12 में निर्दिष्ट राशि का पूरा या उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की लड़ाई के बारे में संदेह या विवाद होने की स्थिति में, हो।

अधिनियम की योजना को पढ़ने के बाद, अब आयुक्त को आगे के दिशानिर्देश देना आवश्यक है कि मुआवजे की राशि को कैसे वितरित किया जाना है। हमने ऊपर देखा कि उभरते ठेकेदारों को भी अधिनियम में 'मालिक' शब्द के दायरे में आएगा। इसलिए, वे भी जमा किए गए मुआवजे के आनुपातिक वितरण के हकदार हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाताओं 1 और 2 ने अनुरोध किया कि देय राशि में से, धारा 23 के तहत आयुक्त द्वारा स्वीकार किए गए सभी दावों को मुआवजे की राशि के हिस्से से नहीं काटा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, तर्क यह था कि जब ट्रैक्टरों की उगाही के कारण राशि का पता लगाया जाता है तो कंपनी द्वारा देय ऋणों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। यानी मुआवजे की रकम में उगाही करने वाले ठेकेदारों की हिस्सेदारी पर मूल मालिक के कर्ज का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए. बताया गया है कि कंपनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर दावे किए गए हैं। यदि उन ऋणों को पहली अनुसूची के कॉलम 5 में निर्दिष्ट सकल राशि से घटा दिया जाता है, तो यह ठेकेदारों को गंभीर

नुकसान पहुंचाएगा और अनुभाग की योजना के साथ हिंसा करेगा और साथ ही उन लोगों के साथ अन्याय करेगा। जो उक्त ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। 'मालिक' शब्द की परिभाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक खदान के संबंध में धारा 2(एन) के अर्थ में एक से अधिक मालिक हो सकते हैं। उनमें से प्रत्येक पहली अनुसूची के कॉलम 5 में दर्शाई गई राशि के एक हिस्से का हकदार होगा। स्वीकृत दावों की कटौती केवल उस मालिक को देय राशि से की जा सकती है जिसके विरुद्ध स्वीकृत दावा संबंधित है। धारा 23 और 24 को पढ़ने का मतलब यह है कि सभी मालिकों को स्वीकृत दावे का बोझ उठाना होगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इन दावों के तहत कौन उत्तरदायी है, धारा के साथ अन्याय करना और धारा की भाषा के साथ हिंसा करना होगा। इन धाराओं को समझने का उचित तरीका यह है कि स्वीकृत दावों को देय राशि से तभी काटा जा सकता है जब ऐसा दावा संबंधित मालिक से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में, केवल मालिक ही जिसने उक्त ऋण वहन किया है, वही इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक मालिक के ऋण की राशि दूसरे मालिक को देय मुआवजे की राशि से नहीं काटी जाए, जिस पर वह पैसा बकाया नहीं है।

उत्तरदाताओं 1 और 2 के विद्वान वकील द्वारा व्यक्त की गई यह आशंका कि उनके मुवक्किलों पर कंपनी के ऋणों के साथ मुआवजे के

हिस्से का बोझ डालकर प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतने चाहिए, अच्छी तरह से स्थापित है। ऐसी अवांछनीय स्थिति पैदा करने वाली धारा नहीं पढ़ी जा सकती. प्रत्येक मालिक के कर्ज का पता लगाने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्ज की पहचान न हो कि किस मालिक पर कितना बोझ पड़ेगा।

इसके बाद धारा 25 ए आती है जो आयुक्त को मालिकों को भुगतान करने में सक्षम बनाती है। यह पढ़ता हैः

> ‘‘25ए कोक ओवन संयंत्रों की कोकिंग कोयला खदानों के मालिकों और प्रबंध ठेकेदारों आदि को नोटिस।
>
> (1) जिन व्यक्तियों के दावे इस अधिनियम के तहत स्वीकार किए गए हैं, उनके दायित्वों को पूरा करने के बाद, आयुक्त अपने पास उपलब्ध धन की राशि को उस तरीके से अधिसूचित करेगा जैसा वह उचित समझे और ऐसी अधिसूचना में एक तारीख निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर के मालिक कोकिंग कोयला खदानें या कोक ओवन संयंत्र, प्रबंध करने वाले ठेकेदार और किसी भी मशीनरी, उपकरण या अन्य संपत्ति के मालिक जो इस अधिनियम के तहत केंद्र

सरकार की कंपनी में निहित थे और जो कोकिंग कोयला खदानों या कोक ओवन के मालिकों से संबंधित नहीं हैं भुगतान के लिए उसके पास आवेदन कर सकते हैं।

(2) जहां उपधारा (1) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, आयुक्त, पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करने के आवेदक के अधिकार के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद, संबंधित व्यक्ति को राशि का भुगतान करेगा और ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति के पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में कोई संदेह या विवाद है, तो आयुक्त धारा 26 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तरीके से आवेदन से निपटेगा।''

यह अनुभाग देनदारियों को पूरा करने के बाद शेष राशि के वितरण से संबंधित है। इसे आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रत्येक मालिक की लड़ाई के अनुसार वितरित किया जाना है और विवाद की स्थिति में विवाद को सक्षम न्यायालय में भेजना होगा।

इस मामले में, पाँच खदानें हैं। अपीलकर्ता सभी पांच खदानों के विशेष मालिक होने का दावा करते हैं। हमने माना है कि उत्तरदाता 1 और 2 भी मालिक हैं। लेकिन वे सभी खदानों पर अधिकार का दावा नहीं करते. कोयला खान राष्ट्रीयकरण कानून (संशोधन) अधिनियम, 1986, 1986 की संख्या 57 द्वारा नव सम्मिलित धारा 26(3) के तहत, इसमें बताए अनुसार राशि का बंटवारा करना आयुक्त का काम है। संशोधित खंड (3) इस प्रकार हैः

> ''(3) जहां पहली अनुसूची के पांचवें कॉलम में निर्दिष्ट राशि कोकिंग कोयला खानों के एक समूह से संबंधित है, आयुक्त के पास ऐसे समूह के मालिकों के बीच ऐसी राशि को विभाजित करने की शक्ति होगी, और इस तरह के विभाजन को करने में, आयुक्त के पास नियत दिन से ठीक पहले के तीन वर्षों के दौरान कोकिंग कोयला खदान में उच्चतम वार्षिक उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा।''

आयुक्त को इस धारा के अनुसार उत्तरदाताओं 1 और 2 द्वारा दावा किए गए खदान के मुआवजे का हिस्सा निर्धारित करना होगा।

हमने ऊपर मुआवजे के बंटवारे में अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों का संकेत दिया है। हमने पाया कि उच्च न्यायालय अपने निष्कर्षों में सही था। इसलिए अपील विफल हो गई है और तदनुसार उत्तरदाताओं 1 और 2 की अपील शुल्क के साथ खारिज कर दी गई है।

एम.एल.ए. अपील खारिज

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री लोचन खिड़िया देवल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)